RAJYA SABHA 1

Shri A. D. MANI: Sir, I have met a number of circus personnel whenever they visit the various town and they feel that wherever such companies contribute to the provident fund that is inadequate and does not cover risks. The contribution to the fund is so inadequate that when they sustain any injury while performing feats they do not get adequate compensation. May I ask the Minister whether he has ever given his mind to this fact of the matter that in the case of circus employees the contribution of the employers should be twice in view of the hazards involved?

Shri Shah Nawaz Khan: Sir, there is a lot in what the hon. has suggested. The nature of their duties, particularly of the artistes who perform, is a hazardous one. But we have to take into consideration the paying capacity of the industry, of the establishment. Many of them are complaining that they are not in a position to pay even this much.

SHRI D. THENGARI: May I know, Sir, the total number of circus employees that are covered by provident fund? How many employees are not getting provident fund and do the Government propose to take action against such of the circus companies which have refused to introduce provident fund?

Shri Shah Nawaz Khan: As I have said, there are ten such establishments which have been brought under the purview of the Act, and only three have complied with it. There may be some others who have escaped notice so far. We are trying to bring them to book and those who do not contribute are proceeded against legally and by other methods.

SHRI M. N. GOVINDAN NAIR: Sir, the Minister in his reply said that it is a roving industry and it is very difficult for them to get hold of them. May I know, Sir, whether the Government will consider the question of taking this industry directly under the Central Government as far as the application of laws is concerned? Another question is that the Minister said that it is a risky job? Will the Government consider insuring their life in view of this?

SHRI P. K. KUMARAN: L.I.C. does not insure them.

SHRI SHAH NAWAZ KHAN: This is a matter which we will have to examine taking into consideration the question of hazards involved in the insurance. But there is the normal compensation which is paid to any workman when he is injured.

AN HON. MEMBER: It is Rs. 35.

SHRI SHAH NAWAZ KHAN: Of course, they do get that. But in view of the special hazardous job they are doing the demand that there should be a special provision is a matter which needs looking into, and we shall examine it.

Shri M. V. BHADRAM: The hon. Minister said that legal and persuasive methods have been used to see that compliance is made. May I know, Sir, in how many cases prosecution has been launched against these companies?

SHRI SHAH NAWAZ KHAN: We moved for some prosecutions but some of them have gone to the High Courts and the cases are still sub judice. That is why we have not been able to proceed with them as vigorously as we would have liked.

एंटीबायोटिक्स प्रोजेक्ट ऋषिकेश से संलग्न टाउनिशप

*844. श्री सुन्दर सिंह भण्डारी: क्या पेट्रोल तथा रसायन मंत्री 5 अगस्त, 1966 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 385 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि एंटीबायो-टिक्स प्रोजेक्ट, ऋषिकेश से संलग्न टाउनिशिप के निकट बनाया गया नाला इस बरस्मत में छ: बार टूट चुना है और जिसके परिणाम-स्वरूप पानी क्वार्टरों के अन्दर चला गया था; और
- (ख) टक्त नाले के निर्माण पर अब तक कुल किनना रुपया खर्च हुआ है?

†[Township attached to Antibiotics Project, Rishikesh

*844. SHRI SUNDAR SINGH BHAN-DARI: Will the Minister of PetroLeum

†[] English translation.

AND CHEMICALS be pleased to refer to the answer to Unstarred Question No. 385 given in the Rajya Sabha on the 5th August, 1966 and state:

(a) whether it is a fact that the breaches occurred six times in the Nullah constructed near the Township attached to the Antibiotics Project, Rishikesh, during the current rainy season as a result of which water entered the residential quarters; and

(b) what is the total amount so far spent on the construction of the said Nullah?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHE-MICALS (SARDAR IQBAL SINGH): (a) There have been no breaches in the drain but during heavy rains, there have been breaches in the earthen bund constructed to prevent outside rain water from entering into the Project township. As a result of such breaches, rain water over-flows the township roads and is drained into the two natural nullahas passing through the project area. Water, however, did not enter the quarters.

(b) The total amount spent on the construction of the drain is Rs. 22,000 approximately.

† [पेट्रोल तथा रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (सरदार इकबाल सिंह): (क) नाले में कोई टूट नहीं हुई किन्तु भारी वर्षा में मिट्टी के बांध में, जोिक बाहर के वर्षा जल को प्रोजेक्ट टाउनिशिप में आने से रोकने के लिये बनाया गया था, टूट-फूट हुई। इस टूट-फूट के फलस्वरूप, वर्षा का पानी टाउनशिप की सडकों के ऊपर बहता है और प्रोजेक्ट क्षेत्र से गुजरने वाले दो प्राकृतिक नालों में बहा दिया जाता है। पानी क्वांटरों मे नहीं घुसा।

(ख) नाले को बनाने में लगभग 22,000 रुपये खर्च हुए।]

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि यह जो बांध, यह जो नाला बनाने का काम है, यह †[] Hindi translation. बार-बार ठेकेदारों के द्वारा वरवाया गया या नहीं और अगर करवाया गया, नो क्या उसी ठेकेदार ने इस काम को बार-बार विया और उसके लिये अलग-अलग प्रकार से उसको रुपया अदा किया गया?

सरदार इकबाल सिंह: इस बात की इफिमिशन तो हमारे पास नहीं है लेकिन जहां तक बांध का सवाल है जिस जगह बीच हुई है, वह बांध दी गई है। किस ठेकेदार से कराया गया इसके लिये अगर सेपरेट नोटिस दें, तो बना सकना हूं।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी. प्रश्न में इस बात का साफ मकेन है और में समझता हूं नि यह सूचना मुझे इस समय मिलनी चाहिये थी। मेरा दूसरा निवेदन यह है कि क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानवारी है कि केवल ये नाले की ही बात नहीं, सारे टाउनिशिप में कहीं भी पानी के निकलने के लिये नालियों की व्यवस्था नहीं है और नाला के टूटने की वजह से भी और नालियों के न होने के कारण भी लगभग सारे टाउनिशिप में बरसात के दिनों मे पानी भरा रहता है और अगर वहां इस प्रकार की परिस्थिति. है, तो मंत्री महोदय वहा के ड्रेनेज की व्यवस्था को ठीक करवाने के लिये कब तक बन्दोबस्त कर लेंगे?

सरदार इकबाल सिंह : जहां तक इस टाउनिशिप का ताल्लुक है, वहा से तीन नाले नैचुरल कोर्स में गुजरते हैं और दो नालों का पानी वह बिलक्ल अपने आप में ले सकते हैं और उनमें कोई जरूरत नहीं बांघ लगाने की या उनको किसी तरह रोकने की, और जहां तक तीमरे नाले का ताल्लुक है, पहले इसका पानी बहुत फैल जाया करता था, तो उस पर एक अर्देन बांध, एक मिट्टी का बांघ बनाया गया। अब उसके बाद सारे कैचमेंट एरिया में कितनी बरसात होती है, कितनी ज्यादा से ज्यादा हो सकती है, इस सबको देखने के सिलमिले में एक स्कीम बनाई जा

रही है और कोशिश की जायगी कि जो पानी वहां से गुजरता है, वह नाले में से गुजर जाय। इस सिलिसिले में गवनंमेंट ने एक स्कीम बनाई है लेकिन मुकम्मल तार पर जब तक इस बात का पता न चल जाय कि कैचमेंट में पानी गुजरने की कितनी कैपेनिटी है। उस बक्त तक स्कीम लागू करना मुनासिब नहीं होगा; क्योंकि ज्यादा पानी हो जाय, तो सारी स्कीम फेल हो जाय। लेकिन उस सिलिसिले में मुकम्मल स्कीम बनाई गई है।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी: मेरा निवेदन पानी निकालने के सम्बन्ध में मकानों के सामने की नालियों से भी था और वह समस्या भी अभी उस इलाके में बनी हुई है, पानी निकलने का अभी तक कोई इंतजाम नहीं है, नालियां नहीं हैं।

सरदार इकबाल सिंह: जहां तक मकान के सामने नालियों का सवाल है, तो नाला जो फैल कर जाता था, उसको एक शक्ल में बांध दिया गया है और जब नाले में पानी का प्रेशर ज्यादा होता है, तो कुदरनी तौर पर जो ऊपर का पानी है, वह उतनी जल्दी नहीं उसमें जा सकता; क्योंकि नाले का प्रेशर पहले से ही कैचमेंट एरिया से आता है। लेकिन जहां तक नालियों का सवाल है, वह भी उम स्कीम में शामिल है कि नालियां भी वनाई जांय और वे उसमें से गुजर सकें।

श्री दत्तोपन्त ठॅगड़ी: क्या सरकार के पास यह जानकारी है कि ऋषिकेण प्रोजेक्ट में कितने मकान ऐसे हैं, जो मनुष्यों के रहने के योग्य नहीं हैं और अगर नहीं हैं, तो क्या यह जानकारी प्राप्त कर के सरकार हमे आश्व-वासन देगी कि उनमें से ऐसे मकान जो मनुष्यों के रहने के योग्य नहीं हैं, उनको मनुष्यों के रहने के योग्य बनाने का यन्त किया जायगा।

सरदार इकबाल सिंह : जहां तक ऋषिकेश के मकानों का ताल्लुक है, ये तो नये बनें हैं और आदमियों के रहने के लिये बनाये गये हैं और बिलकुल नई सुविधायें उसमें दी हैं। जहां तक नालें के पानी का ताल्लुक है, वह पहले वहां से निकला और रेलवे से भी कहा कि वह अपने ढंग से ड्रेनज बनायें और वह ड्रेनज ऋषिकेश प्रोजेक्ट से भी जायगा, तो उस सिलिसिले में अगर कोई बात होती है, तो मैं जरूर बता दूं, लेकिन मकान का क्या बनाऊं।

प्रो० सत्यक्षत सिद्धान्तालंकार : जब भी कोई शहर बनता है, तो नालियां पहले बना करती है, ऐसा नहीं होता कि मकान पहले बन जायं और खाम तौर पर ऋषिकेश का जो टाउनिशप बना हुआ है, वहां बड़े अच्छे-अच्छे भवन भी हैं, तो आप कहते हैं कि नालियों के लिये अब एक अलग योजना बन रही है। मकान पहले बने और अब नालियों की योजना है। मकान पहले बन जायें नालियां बाद में बनें।

सरदार इकबाल सिंह : जहां तक ऋषिकेश का ताल्लुक है, यह वहां बिलकुल हिमालय से शुरू होता है, वहां की नैचुरल ज्योग्रफी इस किस्म की है कि कुछ-कुछ नैचुरल नाले हैं, ड्रेनेज हैं, जो कि इस प्रोजेक्ट में से गुजरते हैं। उसके बाद जहां तक एक नाले का सवाल था, जिसका पानी फैल कर वहां जाता था, उसके टेम करने के लिये उस पर अर्देन बांध बनाया गया है, उसको और चौड़ा करने के लिये स्कीम बनी है : : :

प्रो॰ सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार : जो नालियां अब तक नहीं बनीं वह मैने पूछा, यह टाउनिशिप के लिये हैं।

सरदार इकबाल सिंह: एक मिनट जरा सुन लीजिये। जहां तक टाउनिशप का ताल्लुक है, तो टाउनिशप में जितना पानी आता है, वह फैल कर जाता था, वह इस नाले से गुजार दिया जाता था, लेकिन इस दफा सबसे ज्यादा बरसात हुई, इतना पानी पहले नहीं हुआ, रेलवे लाइन भी टूट गई या उखड़ गई इस दफा इतनी बरमात हुई और इस तरह पहले सालों मे नहीं हुई, इसलिये ऐसा हो गया है जहां तक यह कि टाउनिशप में नालियां नहीं है, तो धह एक और बात है।

Oral Answers

POLICE OFFICERS IN DELHI

- *845. SHRI B. D. KHOBARAGADE: Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:
- (a) the number of police officers in Delhi who have been granted permission to enroll in colleges during the current academic session;
- (b) the number of those police officers who have been refused such permission together with the number of Scheduled Castes police officers included therein; and
 - (c) the reasons for such refusal?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI V. C. SHUKLA): (a) 161.

- (b) 21 including five belonging to Scheduled Castes.
- (c) Permission in these cases was refused in the exigencies of public service.
- SHRI B. D. KHOBARAGADE: May I know the number of police officers who have been allowed to join the post-graduate, namely, the Masters degree or the Law degree courses and the number of Scheduled Caste Officers who have not been allowed to join?
- SIRI V. C. SHUKLA: Permission was given to 161 officers and men of the Police Services. I do not have the break-up of the figures as to how many of these were allowed for the post-graduate course and how many for the under-graduate courses.
- Shri B. D. KHOBARAGADE: May I know whether it is a fact that some of the Scheduled Caste officers had asked for permission and they had given an assurance that they would discharge their duties to the satisfaction of their superior officers because they would be going only to the evening classes and that it would not inter-

fere with their day-to-day work and their cases were recommended by their immediate superior officers and in spite of that they have not been given permission?

SHRI V. C. SHUKLA: Whenever such applications are received, the officer concerned has to see whether the duties allotted to a particular officer would be interefered with if such permission is given and only when it is found that the duties allotted to a particular officer who asks permission for joining the classes will suffer, that such permission is not given. As far as the Scheduled Caste members of the service are concerned, no discrimination is made that if he is a Scheduled Caste he will be or will not be given the permission.

Shri B. D. KHOBARAGADE: May I know whether it is not the declared policy of the Government that the cases of Scheduled Caste Officers should be considered sympathetically and all kinds of facilities should be provided to them so that they can make progress? In view of this proclaimed policy of the Government may I know whether any injustice has been done while granting or refusing permission to the Scheduled Caste officers in Delhi and, if so, if any such case is brought to the notice of the Government, whether such grievances would be redressed?

SHRI V. C. SHUKLA: Yes, it is our policy that we should give the most sympathetic consideration to such applications received from the Scheduled Caste officers and if such cases are brought to our notice, we shall definitely grant them.

Shri M. M. DHARIA: While appreciating the efforts of the Ministry to educate the police officers, may we know what efforts are being made by the Government to educate and train the police officers so that they should behave with the public with humanitarian considerations in our democratic set-up?

SHRI V. C. SHUKLA: Training is given to the Police Forces and this question relates to other educational courses which are run by the various night schools and morning schools and if attending such classes do not interfere with their normal duties, this permission is freely given.